समुचित भागीदारी- समावेशी लक्ष्य

–डॉ भारती प्रवीण पवार

"आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्" यानी निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया था। 'सबका साथ, सबका विकास' से प्रारम्भ प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए बीते आठ वर्षों में राष्ट्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' तक सुनहरी यात्रा करते हुए नौवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक वर्ष के दौरान मुझे भी इस यात्रा में मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के रूप में सहयात्री होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन के अवसर पर अपने संकल्प को लोकतंत्र को समर्पित किया।

आज जब दुनिया एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट से उबरने के लिए भारत की ओर देख रही है, तब प्रधानमंत्री का सक्षम नेतृत्व ही दिग्दर्शन के लिए एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही माना कि नए भारत का सपना, एक सशक्त और समर्थ भारत, तब तक साकार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक नागरिक सशक्त न हो और राष्ट्र निर्माण के मिशन में योगदान देने में सक्षम न हो।

इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना *आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना* का उद्देश्य इसका विस्तार 50 करोड़ से अधिक लोगों तक करने का है। ये वे लोग हैं, जो वर्तमान में किसी भी सरकारी या निजी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर नहीं हैं। इस तरह भारत दुनिया की पहली व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की दिशा में बढ़ रहा है। वर्तमान में 18 करोड़ 43 लाख से अधिक (नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में शामिल हो चुके हैं। यह योजना हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यही नहीं, 25 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया *पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन* अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। इसका उद्देश्य उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भारत की क्षमता को एक बहुत ही आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में एक आदर्श बदलाव लाएगा तथा इसे और अधिक सक्षम बनाएगा।

इसी तारतम्य में पिछले एक वर्ष में चिकित्सा शिक्षा के सुधारों को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिए गए–चाहे वो ढांचागत हों या फिर मानव संसाधन से सम्बंधित, देश के प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या मेडिकल स्नात्तक और स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने का विषय हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनको पूरा करने की निरंतर कोशिश की है। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखते हुए कहा था कि 'देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया।

स्वच्छ भारत अभियान से लेकर *आयुष्मान भारत* और अब *आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन* तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी पहल का हिस्सा हैं। "प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि भारत सरकार महत्वाकांक्षी ज़िलों में मेडिकल कॉलेजों के साथ–साथ 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 से ज़्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के उन्नयन के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आगमन के साथ, अतीत की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान किया गया।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर, 2021 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,01,319 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। इस आधार पर देखें तो पंजीकृत एलोपैथिक

डॉक्टरों तथा 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता मानते हुए देश में डॉक्टर–जनसँख्या का अनुपात 1:834 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से बेहतर है। इसके अलावा, देश में 2.89 लाख पंजीकृत दंत चिकित्सक, 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर तथा लगभग 33.41 लाख पंजीकृत उपचर्या कार्मिक भी हैं। यही नहीं, मंत्रालय के सकारात्मक प्रयासों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, शैक्षणिक वर्ष 2021–22 से स्नात्तक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है कि जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और क्षय रोग, वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं कालाज़ार, कुष्ठ रोग आदि जैसे प्रमुख रोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क सेवाओं के प्रावधान हेतु एनएचएम के तहत प्रदान की जा रही सहायता न केवल छूटे हुए और दुर्गम स्थलों पर रहने वाले बच्चों, जिसमें अल्पसेवित और दूरस्थ तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या अपितु सभी जनजातीय–बहुल ज़िले, जिनका समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, तक पहुंचाने के गंभीर प्रयास किए जाएं। साथ–साथ सिकल–सेल रोग के उन्मूलन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएं। त्रिपुरा और मिज़ोरम के दलित जिलों के प्रवास के दौरान लेखिका को यह जानने का सुअवसर मिला कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस प्रकार इन जनजातीय ज़िलों को मिला है।

प्रधानमंत्री ने टीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करके 2025 तक टीबी को खत्म करने का संकल्प लिया था और इस दिशा में *टीबी मुक्त भारत अभियान* शुरू किया गया। क्षय रोग के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया ने टीबी के खिलाफ लड़ाई को एक जन पहल और जन आंदोलन बनाने की अपील की।

भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए देश में कोविड–19 टीकाकरण की खुराक का 100 करोड़ का महत्वपूर्ण आंकड़ा पिछले वर्ष अक्टूबर में ही पार कर लिया था। हर्ष का विषय है कि आप सभी के सहयोग से हम शीघ्र ही 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रहे हैं। *हर घर दस्तक अभियान* ने कोविड टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार पिछले एक वर्ष में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के विषय में सरकार के प्रयासों के चलते प्रेशर स्विंग एडसॉर्पशन (पीएसए) ऑक्सीजन जेनरेशन संयंत्रों को मंज़ूरी दी गई है और इसे देश के हर ज़िले में लगाया जाना है। सभी राज्य इसमें आगे आकर जन स्वास्थ्य केंद्रों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर पीएसए संयंत्र लगाने में सहयोग कर रहे हैं।

हाल ही में नासिक में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नये एलोपैथिक वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे तथा नागपुर के बाद नासिक चौथा शहर होगा जहाँ यह केंद्र शुरू किया जा रहा है। नासिक के सीजीएचएस वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र से शहर के लगभग 71,000 सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित 1.6 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। इससे पूर्व यहाँ के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए मुंबई अथवा पुणे जाना पड़ता था।

हम सब निश्चित रूप से 8 साल की यात्रा पर गर्व व गौरव का अनुभव कर सकते हैं। जहां तक गांव–गरीब–किसान, जनजातीय समुदाय का सवाल है तो सभी भली–भांति जानते हैं कि भारत सरकार हमेशा इसी तबके के लिए समर्पित रही है। पिछले एक–दो वर्षों में जम्मू कश्मीर की जनता ने सहभागी लोकतंत्र को मज़बूत किया है। निसंदेह जम्मू और कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

जनवरी 2018 में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयता प्रदान करके राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना है। महाराष्ट्र और मणिपुर के कुछ ज़िलों के प्रवास के दौरान लेखिका ने पाया कि इन ज़िलों के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, अवसंरचना आदि में उल्लेखनीय सुधार आया है। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल के अंतर्गत केवड़िया, गुजरात में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और उन्हें लेकर राज्यों की नीतियों पर चर्चा हुई। इस शिविर में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऐसे अवसर देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी राह तय करते हैं।

अपार प्रसन्नता का विषय है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया है।* इस निर्णय में महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ समाज के गरीब, उपेक्षित, सीमांत, दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधियों को शीर्ष पद पर बैठाने, सत्ता में समुचित भागीदारी देने और उनमें गौरव एवं आत्मविश्वास भरने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है।

संकल्प से सिद्धि तक के साँझा प्रयास को सफलता का साकार रूप देने की अभिलाषा के साथ आप सभी के लिए एक स्वस्थ और सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोगमुक्त रहें।

(लेखिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 7 जुलाई, 2021 को राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।)

* यह लेख माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने से पहले लिखा गया है।